

**3** महाराष्ट्र ने सराहा छत्तीसगढ़ का कृषि मॉडल

**5** जनसंघर्ष से जननेतृत्व तक का प्रेरक सफर

**7** योग से चेतना और संगीत से समरसता

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 07

प्रति सोमवार, 22 जून 2026

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

## केवल डेढ़ से दो क्विंटल प्रति एकड़ मूंग खरीद रही मप्र सरकार

### कम रेट पर मूंग बेचने पर मजबूर मध्य प्रदेश के किसान

**कवर स्टोरी**  
-विजया पाठक एडिटर

मध्यप्रदेश के किसानों की मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। पहले गेहू को बेचने में किसानों ने परेशानी झेली अब मूंग को लेकर भी वही स्थिति बन रही है। मूंग बेचने पर तो दोहरी मार

बेहतर मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में यही फसल किसानों के लिए परेशानी और घाटे का कारण बनती जा रही है। इस साल स्थिति कुछ अलग नहीं है। खेतों में लहलहाती मूंग की फसल के बावजूद किसानों को मजबूरी में कम दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। इसके पीछे कई आर्थिक, प्रशासनिक और नीतिगत कारण हैं, जिन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी है। मध्य प्रदेश के किसान आज एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं, जहां उत्पादन तो अच्छा है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। मूंग जैसी नकदी फसल, जो कभी किसानों के लिए उम्मीद थी, अब अनिश्चितता और बाजार के दबाव का प्रतीक बनती जा रही है। जब तक MSP पर भरोसेमंद और समय पर खरीद सुनिश्चित नहीं होती, तब तक किसानों को कम दामों पर फसल बेचने की मजबूरी बनी रहेगी। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि कृषि नीति और बाजार संरचना से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। (शेष पेज 2 पर)



**पहले गेहू बेचने में लाईन में लगे**

**अब मूंग की बारी**

पड़ने वाली है। कहीं कहीं पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वह केवल प्रति एकड़ डेढ़ से दो क्विंटल मूंग बेचने पर ही हो रहे हैं। जबकि प्रति एकड़ मूंग 7-8 प्रति क्विंटल पैदा हुई है। ऐसी स्थिति में बाकी की मूंग को किसान कहाँ बेचेगा। स्वाभाविक है मजबूरन बाजार में व्यापारियों को मूंग बेचने पर मजबूर होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, जिसे भारत का "दलहन राज्य" भी कहा जाता है, देश में मूंग (हरी मूंग) उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ के नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, रायसेन, सीहोर और देवास जैसे जिलों में हर साल हजारों किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करते हैं। यह फसल कम पानी में, कम समय में और अपेक्षाकृत

## मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मत्स्य क्रांति

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ अपनी कृषि प्रधान पहचान के लिए लंबे समय से जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां मत्स्य पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मत्स्य क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज यह क्षेत्र केवल एक पारंपरिक व्यवसाय नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आर्थिक उन्नति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का आधार बन चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की आवश्यकताओं को समझते हुए मत्स्य क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। (शेष पेज 2 पर)



## टीकमगढ़ सीएमओ ओमपाल भदौरिया के काले कारनामे

-विजया पाठक

टीकमगढ़ नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीएमओ) ओमपाल सिंह भदौरिया इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले एक साल में ही भदौरिया ने इतने सारे काले कारनामों किये हैं कि जिले के कई राजनीतिक लोगों ने इनके स्थानांतरण की व्यापक मांग की थी। लेकिन भदौरिया ने अपनी पहुंच के चलते स्थानांतरण रूकवा लिया। चर्चा है कि जब उनके स्थानांतरण की मांग जिले के जनप्रतिनिधियों और भाजपा संगठन की ओर से उठी और मामला विभागीय मंत्री तक पहुंचा, तब उनके तबादले की संभावना लगभग तय मानी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार, जैसे ही सीएमओ भदौरिया को इसकी जानकारी मिली, वे भोपाल पहुंचे और उसके बाद



पूरा घटनाक्रम ही बदल गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के स्तर पर मामला रुक गया और स्थानांतरण की पूरी कवायद टंडी पड़ गई। अब सबाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनप्रतिनिधियों, संगठन और मंत्री स्तर पर चल रही चर्चाओं के बावजूद सीएमओ अपने पद पर बने रहे? भदौरिया भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। खुलेआम शासकीय पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। चर्चा यह भी है कि कुछ महीने पहले नगर पालिका अध्यक्ष के हटने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो गई है, जिसके चलते नगर पालिका की अधिकांश प्रशासनिक शक्तियां सीएमओ के हाथों में आ गई हैं। (शेष पेज 2 पर)

**नया में भदौरिया ने किया लगभग 10 करोड़ का भ्रष्टाचार**

(पेज 1 का शेष)

उनके नेतृत्व में शासन द्वारा ऐसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है, जिनसे छोटे और सीमांत किसानों, स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण युवाओं को नए अवसर प्राप्त हुए हैं। आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य पालन को एक लाभकारी उद्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है।

### जशपुर बना सफलता का मॉडल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह जिले जशपुर ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप जिले में पिछले 22 महीनों के दौरान 22 हजार 805 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। यह उपलब्धि केवल उत्पादन के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हजारों किसानों और मत्स्यपालकों की आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जशपुर जिले में मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ मत्स्य बीज उत्पादन और संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में 18.50 करोड़ रॉयन, 2.55 करोड़ स्टेज फ्राय तथा 2.94 करोड़ मत्स्य बीजों का संचयन किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।

### हजारों हितग्राहियों को मिला प्रत्यक्ष लाभ

साय सरकार ने यह सुनिश्चित

# मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मत्स्य

किया है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी दृष्टि से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों और जलाशयों का प्रभावी उपयोग किया गया है। लगभग 77.67 हेक्टेयर तालाबों तथा 295.27 हेक्टेयर जलाशयों का पट्टा आवंटित कर मत्स्यपालकों को व्यवसाय विस्तार का अवसर प्रदान किया गया है। इसके साथ ही नाव, जाल, फिंगरलिंग, मत्स्य बीमा, परिवहन एवं विपणन सहायता जैसी सुविधाओं के माध्यम से सात हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इन प्रयासों ने ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए हैं।

### आधुनिक तकनीक से बढ़ा उत्पादन

आज का युग तकनीक आधारित विकास का युग है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण, पीड लाइन, बायोप्लॉक यूनिट, मत्स्य हेचरी और अन्य आधुनिक संरचनाओं की स्थापना के

लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है बायोप्लॉक जैसी वैज्ञानिक तकनीक ने कम स्थान और कम पानी में अधिक उत्पादन की संभावनाएं बढ़ाई हैं। इससे किसानों की उत्पादन लागत कम हुई है और लाभ में वृद्धि हुई है। आधुनिक तकनीक के समावेश से छत्तीसगढ़ के मत्स्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

### प्रशिक्षण और नवाचार पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री साय का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में स्थायी विकास के लिए ज्ञान और कौशल का विस्तार आवश्यक है। इसी सोच के अनुरूप मत्स्यपालकों को देश के विभिन्न राज्यों में अध्ययन भ्रमण और एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जा रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसान वैज्ञानिक मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, मत्स्य बीज उत्पादन, रोग नियंत्रण, संतुलित आहार और विपणन तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे वे आधुनिक चुनौतियों का सामना करने और अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम हो रहे हैं।

### महिलाओं और युवाओं को मिल

### रहा नया अवसर

मत्स्य पालन क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहीं ग्रामीण युवाओं के लिए यह क्षेत्र स्वरोजगार का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा संचालित योजनाओं ने युवाओं को गांव में रहकर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इससे ग्रामीण पलायन में कमी आने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

### आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिल रही गति

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन, रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र निरंतर विस्तार कर रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। आज छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह विकास केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में समृद्धि, आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा का नया अध्याय लिख रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित विकासोन्मुखी नीतियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी योजनाएं मिलकर छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भरता, समृद्धि और ग्रामीण विकास के नए शिखरों की ओर अग्रसर कर रही हैं। मत्स्य क्षेत्र की यह प्रगति निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

### टीकमगढ़ सीएमओ ओमपाल भदौरिया के काले कारनामे

(पेज 1 का शेष)

करोड़ों के विकास कार्यों, प्रशासनिक निर्णयों और फाइलों की कमान अब एक ही कुर्सी के इर्द-गिर्द घूम रही है। ऐसे में इस प्रभावशाली और "मलाईदार" पद को छोड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं बताई जा रही है।

### जब तक एसीएस साहब हैं, तब तक मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता

सूत्रों की मानें तो राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि सीएमओ ओमपाल भदौरिया ने बातचीत के दौरान कथित तौर पर यह तक कह दिया कि- "जब तक एसीएस साहब हैं, तब तक मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।" इस कथित बयान के बाद चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक अधिकारी को अपनी कुर्सी और अपने प्रभाव पर इतना भरोसा कैसे है? टीकमगढ़ में लोग चुटकी लेते हुए कह रहे हैं- "मंत्री बदल जाएं, नेता बदल जाएं, लेकिन सीएमओ साहब की कुर्सी नहीं हिल सकती!" अब यह केवल राजनीतिक चर्चाएं हैं या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है, यह तो संबंधित अधिकारी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन टीकमगढ़ की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी है कि आखिर सीएमओ साहब की ताकत का असली राज क्या है?

### स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक पाने के लिए किए जाते हैं फर्जी फोटोशूट

वार्ड नंबर 06, गोपाल मंदिर के पीछे का नगर पालिका के कर्मचारी नाली पर जाल रखते हैं, फोटो खींचते हैं और तुरंत जाल वापस ले जाते हैं। कमाल है। स्वच्छता सर्वेक्षण पर इस तरह की फर्जी फोटो दिखाकर कब तक नगर पालिका श्रेणी और स्थान प्राप्त करेगी? अभी कुछ दिन पहले भोपाल की टीम टीकमगढ़ आई थी। लोगों ने उनसे कहा था कि कहीं स्वच्छता नहीं है। हमारे मोहल्ले में कचड़े के ढेर रखे हैं। यहां कोई झाड़ू लगाने तक नहीं आता। लेकिन नगरपालिका के अधिकारी अपनी रैंक बढ़ाने में लगे रहे, किसी की नहीं सुनी।

### फर्जी फाइलें बनाकर किया 10 करोड़ का भ्रष्टाचार

टीकमगढ़ की जनता ने नगर पालिका में बदलाव इसीलिए किया था क्योंकि पूर्व से ही नगर पालिका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी। अधिकारी ऐसे फर्जी सर्वेक्षण करवाकर झूठी वाहवाही लूटना चाहती है। लेकिन जनता सब जानती है। टीकमगढ़ नगर पालिका में सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने एक साल में करीब 10 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। यह आरोप टीकमगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पप्पू मलिक ने लगाए हैं। पूरी नगर पालिका का बंटोहार कर दिया है। बताया जा रहा है कि भदौरिया एक-एक काम की पाँच-पाँच फाइलें बनाकर बार-बार फुटकर टेंडर निकालते हैं। 06 अगस्त 2025 से अब तक एक ही ठेकेदार को 22 ठेके दिये गये हैं। यह ऑनलाईन टेंडर प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न है। मतलब साफ है कि ठेकेदार के माध्यम से खुद के फायदे के लिए यह सब फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

# केवल डेढ़ से दो किंवदंल प्रति एकड़ मूंग खरीद रही मप्र सरकार

(पेज 1 का शेष)

### MSP और बाजार भाव के बीच बढ़ती खाई

सरकार हर साल मूंग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करती है, ताकि किसानों को उनकी लागत से कम दाम न मिलें। 2026 के आसपास मूंग का MSP लगभग 8800 प्रति किंवदंल है। लेकिन हकीकत यह है कि मंडियों में किसानों को कई बार 6000 से 7000 प्रति किंवदंल के बीच ही दाम मिल रहे हैं। जब सरकारी खरीद समय पर शुरू नहीं होती, तो किसान मजबूरी में निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेच देते हैं। व्यापारी इसी स्थिति का फायदा उठाकर कम कीमत पर खरीदारी करते हैं।

### खरीदी प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता

किसानों की सबसे बड़ी समस्या सरकारी खरीदी में देरी और अनिश्चितता है। कई बार मूंग की फसल तैयार हो जाती है, लेकिन खरीदी केंद्र शुरू नहीं होते। इससे किसानों को भंडारण की समस्या होती है और वे लंबे समय तक फसल रोककर नहीं रख सकते। कई जिलों में किसान इस वजह से मूंग की खेती छोड़ने तक पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं रहता कि सरकार समय पर MSP पर खरीद करेगी या नहीं।

### निजी मंडियों का दबाव

जब सरकारी खरीद सीमित या देर से होती है, तो पूरा दबाव निजी मंडियों पर आ जाता है। वहां भाव पूरी तरह मांग और आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। जैसे ही नई फसल बाजार में आती है, कीमतें तेजी से गिर जाती हैं। कई जिलों में देखा गया है कि शुरूआती दिनों में भाव ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आवक बढ़ती है, रेट गिरकर लागत के करीब या उससे नीचे पहुंच जाते हैं। इससे किसानों की मेहनत का लाभ विचलितियों और व्यापारियों को मिल जाता है।

### लागत बढ़ने और मुनाफा घटने की समस्या

किसान केवल फसल उगाने में ही नहीं, बल्कि बीज, खाद, सिंचाई, श्रम और परिवहन में भी भारी खर्च करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन सभी इनपुट लागतों में लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन मूंग का बाजार भाव उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। इस असंतुलन के कारण किसान "लागत निकालना" भी मुश्किल समझ रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि अगर फसल MSP पर भी नहीं बिकती, तो वे घाटे में चले जाते हैं। किसानों की एक बड़ी चिंता नीति की अनिश्चितता भी है। कभी खरीद की घोषणा होती है, कभी प्रक्रिया देर से शुरू होती है, तो कभी सीमित कोटा तय कर दिया जाता है। इससे किसान यह तय नहीं कर पाते कि कौन सी फसल लाभकारी रहेगी। मप्र सरकार ने कुछ वर्षों में राज्य ने मूंग की खरीद प्रक्रिया को लेकर

स्पष्टता नहीं दी, जिससे किसानों का भरोसा कमजोर हुआ है और उन्होंने फसल पैटर्न बदलना शुरू कर दिया है। किसानों को उत्पादन जोखिम के साथ-साथ बाजार जोखिम भी झेलना पड़ता है, जिससे यह फसल पहले जैसी "कम जोखिम वाली" नहीं रह गई है।

### छोटे और मध्यम किसानों की सबसे ज्यादा मार

मध्य प्रदेश के ज्यादातर मूंग उत्पादक छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती। ऐसे किसान फसल को लंबे समय तक रोककर नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें तुरंत मंडी में बेचना पड़ता है। यही वजह है कि बड़े व्यापारी और आबूती इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और कम दामों पर खरीद कर मुनाफा कमाते हैं।

### पंजीयन और प्रक्रिया की जटिलता

सरकार ने MSP पर खरीद के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसकी समयसीमा और प्रक्रिया को लेकर भी किसानों में भागदौड़ और भ्रम की स्थिति रहती है। अभी भी कई जगहों पर ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन नहीं हो रहा है। मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर जो "हाहाकार" जैसी स्थिति दिख रही है, उसकी असल वजहें कुछ साफ तौर पर सामने आ रही हैं।

# पहाड़ियों को उनके विकास का उचित हिस्सा मिले: सुवेन्दु अधिकारी

-अमित राय

**जगत प्रवाह.** दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी ने पद ग्रहण करने के बाद दार्जिलिंग पहाड़ियों की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर कुर्सोंग का दौरा किया। मोटिवोट ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अधिकारी ने लंबे समय से लंबित क्षेत्रीय चुनौतियों को संबोधित करने और क्षेत्र के विकास के लिए नए अवसरों को खोलने के उद्देश्य से एक व्यापक रोडमैप पर



प्रकाश डाला। उन्होंने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, आजीविका, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए ठोस योजनाओं का भी खुलासा किया।

उन्होंने कलिम्पोंग में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें डुंगरा में पहले से ही पहचान की गई भूमि है, साथ ही कुर्सोंग, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें बेहतर स्कूलों, डिजिटल कक्षाओं, लड़कियों के छात्रावासों और स्थानीय प्रतिभाओं के पोषण के लिए सुविधाएं शामिल हैं। रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 01 जुलाई 2026 से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना (जी-राम जी) शुरू की जाएगी, जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं के माध्यम से सालाना 125 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करेगी। उन्होंने बेहतर सड़क संपर्क, आपदा शमन और प्रबंधन, पर्यटन बढ़ावा, आपदा तैयारी, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और युवा केंद्रित पहलों सहित प्रमुख विकास प्राथमिकताओं को भी लोगों के समक्ष रखा। साथ ही उन्होंने पूर्वी सीमांत राइफल्स और पश्चिम

बंगाल पुलिस में 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की, इस प्रकार इएफआर पुनरुद्धार सुनिश्चित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ नजदीकी समन्वय का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि पहाड़ियों को उनके विकास का उचित हिस्सा मिले और उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाए।

## महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल ने सराहा छत्तीसगढ़ के कृषि मॉडल को



-शशि पांडे

**जगत प्रवाह.** रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री साय से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के हित में संचालित योजनाओं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहां की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बस्तर की समृद्ध आदिवासी कला एवं संस्कृतिक के प्रतीक बस्तर आर्ट का स्मृति-चिह्न भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार

और राज्य सरकार किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषि निवेश में सहायता, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 141 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है, जो देश में धान खरीदी के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में लगभग 2700 धान उपार्जन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से धान की खरीदी की जाती है। धान के सुरक्षित भंडारण के लिए संग्रहण केंद्रों और गोदामों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया

गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए पंजीयन से लेकर धान तौल, परिवहन और भुगतान तक की प्रक्रिया को तकनीक आधारित और सरल बनाया गया है। किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने कृषक उन्नति योजना सहित राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महाराष्ट्र के विधायक डॉ. परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, राजू कारेमोरे एवं संजय पुराम, छत्तीसगढ़ मार्केटिंग के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

## मानसून की देरी से खरीफ बोनी प्रभावित: किसान बोले- 20 दिन की देरी होने की संभावना, फसल उत्पादन भी घटने की आशंका

-बद्रीप्रसाद कौरव

**जगत प्रवाह.** बरसिंहपुर। जिले में इस वर्ष मानसून की देरी के कारण खरीफ फसलों की बोनी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सामान्यतः जून के शुरुआती दिनों में ही बोनी से जुड़ी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस साल पर्याप्त वर्षा न होने के कारण यह पूरी प्रक्रिया पिछड़ गई है। समय पर बारिश न होने से किसानों में इस बात की चिंता बढ़ गई है कि इसका फसल उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

**खेतों को तैयार करने में जुटे किसान**

क्षेत्र के बहुवार गांव के किसान जगदीश ठाकुर और रघुवर ठाकुर ने बताया कि इस बार मानसून में लगभग 20 दिन की देरी होने की संभावना नजर आ रही है। इसके चलते अभी तक खेत पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं। फिलहाल किसान खेतों की जुताई और अन्य प्रारंभिक कृषि कार्यों को निपटाने में लगे हुए हैं। किसानों का कहना है कि आमतौर पर इस समय तक अधिकांश क्षेत्रों में बोनी का काम शुरू हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक अटका हुआ है।

**उत्पादन और कटाई पर पड़ेगा असर**

किसानों के अनुसार, अगर आगे भी मौसम का यही रुख रहा और अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनीं, तो इसका सीधा असर फसलों की बुढ़ि, कुल उत्पादन और अंततः कटाई के समय पर पड़ सकता है। देरी से बोनी होने के कारण फसलें मौसम के बाद के चरणों (जैसे कम नमी या टंड का जल्दी आना) से प्रभावित हो सकती हैं, जिससे कुल पैदावार घटने का खतरा बना रहेगा।

**कृषि विशेषज्ञों की राय**

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, खरीफ फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए सही समय पर वर्षा होना और समय पर बोनी का कार्य पूरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि आने वाले दिनों में अच्छी और पर्याप्त बारिश होती है, तो स्थिति में काफी हद तक सुधार संभव है। फिलहाल, क्षेत्र के किसान टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं और मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी फसलों की बोनी शुरू कर सकें।

## करंट लगने से प्राचीन शंकर मंदिर परिसर में नदी की मौत

-प्रमोद बरसले

**जगत प्रवाह.** टिहरील। नगर में वार्ड क्रमांक 08 स्थित प्राचीन शंकर मंदिर परिसर में करंट की चपेट में आने से नदी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षी राजेश नाथ ने बताया कि मंदिर परिसर में लोहे के पाइप से बनी बाउंड्री में अचानक बिजली का करंट आया। वहां बैठा नदी उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिजली कंपनी और नगर परिषद को सूचित किया। जांच में

हादसे का मुख्य कारण पाया गया कि पास स्थित कांजी हाउस के समीप लंगे बिजली के खम्भे की तान सपोर्ट नगर परिषद द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन को छू रही थी। यह पाइप लाइन आगे जाकर मंदिर परिसर के लोहे के पाइपों के सम्पर्क में थी। माना जा रहा है कि नदी ने पाइप लाइन के खुले हिस्से को चाटने का प्रयास किया होगा जिससे उसे करंट लगा और घबराहट में बाउंड्री से टकराने पर पूरी बाउंड्री में करंट फैल गया। उक्त संबंध में नया सीएमओ प्रियव्रत बकोरिया का कहना है कि घटना अत्यंत दुखद है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

सम्पादकीय

# युद्ध विराम: क्या पश्चिम एशिया में शांति की नई शुरुआत होगी?

पश्चिम एशिया लंबे समय से वैश्विक तनाव, सामरिक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक संघर्षों का केंद्र रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच समय-समय पर पैदा होने वाले तनाव ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों पर भी असर डाला है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम या तनाव कम करने की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है।

ईरान और अमेरिका के संबंध पिछले चार दशकों से अविश्वास और टकराव से भरे रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ और विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार मतभेद बने रहे हैं। कई बार हालात ऐसे बने जब दुनिया को बड़े युद्ध की आशंका सताने लगी। हाल के तनावों ने भी यही संकेत दिए कि यदि समय रहते कूटनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो पूरा क्षेत्र गंभीर संघर्ष की चपेट में आ सकता है।

युद्ध विराम की घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संवाद और कूटनीति के लिए नए द्वार खोलती है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। संघर्ष में चाहे कोई भी पक्ष विजेता घोषित हो, सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास को ही होता है। युद्ध के कारण हजारों परिवार प्रभावित होते हैं, निवेश रुक जाता है और विकास की प्रक्रिया वर्षों पीछे चली जाती है।

अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति है, जबकि ईरान पश्चिम एशिया का एक प्रभावशाली क्षेत्रीय खिलाड़ी है। दोनों के बीच टकराव का सीधा प्रभाव वैश्विक तेल बाजार पर पड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर विश्व के बड़े हिस्से का तेल परिवहन होता है। यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आती है, जिसका असर भारत सहित दुनिया के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। युद्ध विराम से वैश्विक बाजारों को राहत मिलने

की संभावना बढ़ती है और निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होता है।

भारत जैसे देशों के लिए भी यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ रणनीतिक एवं आर्थिक संबंध हैं। एक ओर अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक और तकनीकी साझेदार है, वहीं दूसरी ओर ईरान ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए भारत हमेशा संवाद, शांति और कूटनीतिक समाधान का समर्थक रहा है।

हालांकि केवल युद्ध विराम को स्थायी समाधान मान लेना जल्दबाजी होगी। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध विराम अस्थायी साबित हुए हैं और थोड़े समय बाद तनाव फिर बढ़ गया। इसलिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष केवल हथियारों की आवाज शांत करने तक सीमित न रहें, बल्कि मूल विवादों के समाधान के लिए गंभीर और सतत बातचीत करें। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और परस्पर विश्वास बहाली जैसे मुद्दों पर ठोस पहल किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका भी इस समय महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व समुदाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि शांति प्रक्रिया केवल औपचारिक घोषणा तक सीमित न रहे, बल्कि उसे दीर्घकालिक स्थिरता में बदला जाए। कूटनीति को सफलता तभी मानी जाएगी जब क्षेत्र के नागरिक भय और अनिश्चितता से मुक्त होकर सामान्य जीवन जी सकें। युद्ध विराम को शांति की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि उसकी ओर बढ़ाया गया पहला कदम माना जाना चाहिए। यदि दोनों देश संघम, संवाद और पारस्परिक सम्मान का मार्ग अपनाते हैं तो यह न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए सकारात्मक संदेश होगा। आज आवश्यकता शक्ति प्रदर्शन की नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व और रचनात्मक कूटनीति की है। दुनिया को युद्ध नहीं, शांति चाहिए; टकराव नहीं, सहयोग चाहिए। ईरान-अमेरिका युद्ध विराम इसी आशा की एक महत्वपूर्ण किरण बन सकता है।

# सियासी गहमागहमी

क्या मंत्र कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं जीतू पटवारी? मध्यप्रदेश कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही हैं। हालांकि अभी तक पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, लेकिन संगठन की लगातार चुनावी चुनौतियों और अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण प्रदेश संगठन में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा स्वाभाविक मानी जा रही है। जीतू पटवारी को कांग्रेस ने युवा और आक्रामक नेतृत्व के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर मुखर विपक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस को अभी भी वह मजबूती नहीं मिल सकी है जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की चुनौती भी समय-समय पर सामने आती रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व आगामी चुनावों और संगठन विस्तार की रणनीति को ध्यान में रखते हुए नए समीकरणों पर विचार कर सकता है। यदि पार्टी को लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन से संगठन को नई ऊर्जा मिल सकती है, तो बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

भोपाल में धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी और सियासी संकेत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद को लेकर की गई चुटकी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। भारतीय राजनीति में अक्सर नेताओं की हल्की-फुल्की टिप्पणियां भी बड़े राजनीतिक संदेशों के रूप में देखी जाती हैं और धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेता के बयान को भी इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। राजनीति में हास्य और व्यंग्य संवाद का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब कोई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच से किसी सांसद या नेता को लेकर टिप्पणी करता है तो उसके कई अर्थ निकाले जाते हैं। भाजपा जैसे अनुशासित संगठन में नेताओं के बयान सामान्यतः सोच-समझकर दिए जाते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक विश्लेषक इस टिप्पणी के पीछे के संकेतों को समझने का प्रयास करें। हालांकि लोकतांत्रिक राजनीति में स्वस्थ हास्य और सौहार्दपूर्ण संवाद का भी अपना महत्व है। यदि टिप्पणी केवल मित्रतापूर्ण वातावरण में की गई हो तो उसे अनावश्यक राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं यदि इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है तो आने वाले दिनों में उसके संकेत संगठनात्मक गतिविधियों और राजनीतिक घटनाक्रमों में दिखाई दे सकते हैं।

# हपते का कार्टून



# ट्वीट-ट्वीट

नागपुर का एक बच्चा एक महीने से NEET re-exam की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने admit card उड़ाने दे दिया। उसका सेट गिरा - अब धांधली। न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वयत बचा है। वो रातभर रोता रहने, और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है - क्या इस तनाव की कारण भी की जा सकती है? -राहुल गांधी



मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक महीने पहले ट्रांसफर के मौसम में अट्टाघार का पहाड़ खड़ा कर दिया है। "पैसा दो, काम लो" के मंत्र का जाप करते हुए हर पोस्ट पर ट्रांसफर का खुला रेट एनपी में चला। अगर सारे तबादलों में हुए लेन देन की ईमानदारी से जांच हो तो कई सौ करोड़ का खोटाला सामने आयेगा। -कमलनाथ



## राजवीरों की बात

## शुभेंदु अधिकारी: जनसंघर्ष से जननेतृत्व तक का प्रेरक सफर

समता पाठक/जगत प्रवाह



भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने संघर्ष, संगठन क्षमता और जनसंपर्क के बल पर विशेष पहचान बनाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी ऐसा ही एक नाम हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन हर चुनौती का सामना करते हुए स्वयं को राज्य की राजनीति के प्रमुख नेताओं में स्थापित किया। आज वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी नगर में हुआ। उनका परिवार लंबे समय से सांख्यिक जीवन और राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता सिरिसि अधिकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि रहे हैं। राजनीतिक यातावरण में पले-बढ़े शुभेंदु अधिकारी ने युवावस्था से ही जनसेवा और सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाई।

उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र और युवा राजनीति से की। प्रारंभिक वर्षों में वे कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन बाद में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बने तृणमूल कांग्रेस दल के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। संगठन निर्माण, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जनआंदोलनों को दिशा देने की उनकी क्षमता ने उन्हें शीघ्र ही राज्य राजनीति का प्रभावशाली चेहरा बना दिया। वर्ष 2007 में नंदीग्राम आंदोलन ने शुभेंदु अधिकारी को व्यापक पहचान दिलाई। भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए इस आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। किसानों और ग्रामीणों के अधिकारों की आवाज बनकर उन्होंने जनसमर्थन अर्जित किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नंदीग्राम आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शुभेंदु अधिकारी को जननेता के रूप में स्थापित किया।

शुभेंदु अधिकारी ने सांसद और विधायक दोनों रूपों में जनता का प्रतिनिधित्व किया। तमकुल लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहने के बाद उन्होंने विधानसभा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। राज्य सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने परिवहन, सिंचाई तथा जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला। उनके कार्यकाल में कई विकास योजनाओं को गति मिली। वर्ष 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह निर्णय पश्चिम बंगाल की राजनीति को सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना गया। इसके बाद वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी विशेष पहचान दिलाई। नेता प्रतिपक्ष के रूप में शुभेंदु अधिकारी सरकार की नीतियों पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं। कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता, विकास और जनहित के मुद्दों को वे लगातार उठाते रहे हैं। समर्थकों के अनुसार उनकी सबसे बड़ी विशेषता जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहना और संगठन को मजबूत बनाए रखना है।

शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक जीवन संघर्ष, जनसंपर्क और नेतृत्व क्षमता का उदाहरण है। उन्होंने स्वयं को केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाले नेता के रूप में स्थापित किया है। पश्चिम बंगाल की समकालीन राजनीति में उनका नाम उन नेताओं में शामिल है, जिनकी भूमिका आने वाले वर्षों में भी राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण मानी जाएगी।

## विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहा मध्य प्रदेश, खट्टर ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां



## -दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. उज्जैन। इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के भूमिपूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की असली तस्वीर है। फतेहाबाद-चंद्रावतीगंज में आयोजित कार्यक्रम में खट्टर ने कहा कि इंदौर और उज्जैन सिर्फ दो शहर नहीं हैं, बल्कि मालवा की आर्थिक और धार्मिक पहचान हैं। ऐसे में दोनों शहरों को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने वाली यह परियोजना आने वाले

वर्षों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इंदौर व्यापार, उद्योग और रोजगार का बड़ा केंद्र है, जबकि उज्जैन आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की राजधानी है। जब इन दोनों शहरों का संगम मजबूत होगा तो इसका सीधा लाभ पूरे मालवा क्षेत्र को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की जो परिकल्पना कर रही है, वह भविष्य में विकास का नया मॉडल बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि करीब 48 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के बनने से दोनों शहरों के बीच दूरी और यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निवेश आएगा और

नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने इसे सिर्फ सड़क परियोजना नहीं बल्कि आर्थिक विकास का बड़ा माध्यम बताया।

## हितग्राहियों को मिली हजारों करोड़ की सौगात

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए। खट्टर ने बताया कि हजारों परिवारों को मकान सौंपे गए हैं और विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं के जरिए प्रदेश के शहरों को नई पहचान मिल रही है।

## मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में बड़ी और कड़ी कार्रवाई की

## -प्रमोद कुमार

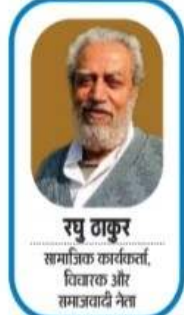
जगत प्रवाह. देहरादून। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त हरिद्वार नगर निगम वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं, तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह को अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के समुचित निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध दीर्घ शास्ति अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, उस समय कार्यरत एसडीएम अजयवीर सिंह के विरुद्ध पर्यटना प्रविष्टि

## भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

दर्ज करने तथा उनकी तीन घंटे की वृद्धियां रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले के सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी सहित कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था।

इसके बाद विशेष जांच और ऑडिट के माध्यम से पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल कराई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि शासन-प्रशासन सर्वोपरि है तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी। धामी सरकार की इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है, जिसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनधन के दुरुपयोग और पद के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

# स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी से दूर भागती सरकार



**रघु ठाकुर**  
सामाजिक कार्यकर्ता,  
विचारक और  
समाजवादी नेता

मई के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये जिनकी विवेचना जरूरी है। सरकार ने तय किया है कि अब देश के 15 लाख सरकारी स्कूलों का संचालन एक समिति करेगी। जिसमें प्राचार्य शिक्षकों के अलावा 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों के अभिभावक याने तीन चौथाई सदस्य अभिभावक



जाये। परंतु यह नहीं सोचा कि अब इन शालाओं के विद्यार्थी कहाँ जायेंगे। और ये शाला भवन कब बनेंगे। मद्र के सागर जिले के सानीधा गाँव में मैं पिछले साल दौरे पर गया था, सानीधा गाँव सागर जिले का एक बहुत बड़ा गाँव है और उस गाँव की शाला में आसपास के कई गाँव के विद्यार्थियों जिनकी संख्या लगभग 3000 थी पढ़ते थे। यह शाला भवन तो टूट गया, नया बना नहीं, सरकार ने धन राशि दी नहीं और अब बच्चे खुले मैदान में पढ़ रहे हैं। यह तो मैंने एक घटना उद्घृत की है, न जाने इस प्रकार के कितने स्कूल मद्र व देश में होंगे। मद्र में सरकारी स्कूलों में 52 हजार शिक्षक के पद खाली हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 47 हजार शिक्षक के पद खाली हैं और 7 हजार स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है। ऐसी स्थिति अन्य राज्यों की भी है। बिहार में 2.75 लाख, झारखंड में लगभग 1 लाख, प.बंगाल में 77000, शिक्षकों के पद खाली हैं। मद्र के जिन 7 हजार स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है, उनमें 2 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं, कल्पना कीजिये कि इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी? मजेदार बात यह है कि, 463 ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं पढ़ता है, परंतु सरकार के अनुसार इनमें 223 शिक्षक पदस्थ हैं। याने बगैर किसी पढ़ाई के शिक्षक वेतन ले रहे हैं। यह स्थिति अकेले मद्र की नहीं है बल्कि लगभग देश के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से की है।

होंगे। यह भी निर्णय किया कि 30 लाख रुपये तक के जो स्कूल-भवन में सार्वजनिक कार्य होंगे वह कार्य यह समिति ही करायेंगी, किसी अनुमति की ऊपर से आवश्यकता नहीं होगी। तथा अब ये शिक्षण संस्थायें सीएसआर से याने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सार्वजनिक या निजी उद्योगों से मदद ले सकते हैं। ऊपरी तौर पर यह निर्णय सत्ता के विकेन्द्रीकरण का लगता है और शालाओं के संचालन की कुंजी की चाबी मुख्यतः अभिभावकों की समिति को देते हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि धन संबंधित चौक आदि पर प्राचार्य के साथ-साथ अभिभावक समिति के अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होंगे। निःसंदेह यह निर्णय छात्रों के सबसे शुभचिंतक उनके अभिभावकों को अधिकार देते हैं। परंतु शिक्षा क्षेत्र की जो वास्तविकतायें हैं उनके आधार पर भी सोचना होगा। क्योंकि सरकार का कार्य जमीन पर कम प्रचार पर अधिक चलता है। जैसे कुछ दिनों पहले यह कहा गया था कि नई शिक्षा नीति में प्रति छात्र बजट में 130 प्रतिशत की वृद्धि की गई, याने लगभग सवा गुना परंतु सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नई शिक्षा नीति के बाद कितने स्कूल बंद हुए और कितने छात्रों की संख्या घटी है इसका उल्लेख नहीं किया गया। जबकि तथ्य यह है कि देश में लगभग डेढ़ से दो लाख स्कूल बंद कर दिये और छात्रों की संख्या बहुत घट गई। राज्य सरकारों ने यह तर्क दिया है कि स्कूलों में छात्र नहीं थे या नगण्य थे इसलिए बंद कर दिये गये, तब इस पर भी विचार होना चाहिए कि स्कूलों में छात्र कम हुए तो इसमें किसकी जवाबदारी है। क्या यह तथ्य नहीं है कि देश के 1 लाख स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक, यहां तक की सैकड़ों हजारों स्कूलों में मात्र एक-एक शिक्षक से स्कूल चलता था और शिक्षक गाँव की जगह दूर शहर में रहते थे। इस प्रकार के हालातों के चलते लाचार होकर अभिभावकों को निजी शिक्षण, टुकानों में शरण लेनी पड़ी और जिनकी आर्थिक क्षमता अच्छी नहीं थी उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये। 2020 में नई शिक्षा नीति आने के बाद सत्ता के प्रचारकों ने यह लिखना शुरू कर दिया कि शिक्षा में बहुत विकास हो रहा और अब सरकार के समक्ष शिक्षा को अंतरराष्ट्रीयकरण की चुनौती है। अब यह भी लिखा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद पहले के मुकामले इन स्कूलों में खेलों के मैदान की सुविधा हो गई जबकि यह पूर्णतः झूठ है। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया कि खेल मैदानों व जिम आदि की साझेदारी की व्यवस्था हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप जिन स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं उन्हें दूसरे स्कूलों के साथ खेल मैदान की साझेदारी दिखा दी तथा सरकारी आंकड़ा संतुष्ट हो गया।

बाकायदा घोषित कर 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में आने की अनुमति दी है। पूर्व से ही विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अब सरकारी विवि और निजी विवि लगभग बराबर ही है। या हो सकता है कि निजी विवि कुछ ज्यादा हो। आज देश में लाखों सरकारी स्कूलों के शाला भवन संख्या में अपर्याप्त है और जो हैं उनमें आवश्यक सुविधायें नहीं हैं। हजारों तो खंडहर में बदल गये। पिछले साल बरसात में मद्र के सागर जिले के शाहपुर कस्बे में एक क्षतिग्रस्त शाला भवन की दीवार गिरने से कई छात्रों की मौत हो गई और सरकार ने अपनी कार्यवाही बताने के लिये आदेश जारी कर दिया कि जो क्षतिग्रस्त शाला भवन हैं उन्हें गिरा दिया

अब यह समितियाँ बन जायेंगी जिनमें 75 प्रतिशत अभिभावक समिति में सदस्य होंगे परंतु जब स्कूल के भवन के लिये सरकार ने बजट ही नहीं दिया तब यह स्कूल कैसे बनेंगे? कहाँ से 30 लाख रुपये खर्च करेंगे, (जब पैसा ही नहीं होगा) कुल मिलाकर सरकार को एक बहाना अवश्य मिल जायेगा कि अब जवाबदार हम नहीं हैं बल्कि यह समितियाँ हैं। 31 मई के अखबारों में खरगोन जिले की खबर छपी है जहाँ अनेक स्कूलों के भवन जर्जर हैं या गिर गये हैं। नये भवन बनाने का सरकार ने जो पैसे की घोषणा की वह नहीं पहुँचा, जबकि जून माह शुरू हो रहा है याने बारिश सिर पर है, क्या ये भवन बन सकेंगे? इनमें प्रवेश लेने वाले छात्र वहीं पढ़ेंगे? यही स्थिति शिक्षकों के बारे में होगी। क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन आदि सरकार देती है परंतु अब सरकार कहेगी कि स्कूलों में बगैर शिक्षक या शिक्षकों की कमी या अन्य कारणों से जो गिरावट होगी उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है बल्कि इन समितियों की जवाबदारी है। याने अपराधी सरकार बच जायेगी तथा निर्दोष प्राचार्य व समितियों के सदस्य गुनाहगार बन जायेंगे।

## आर्थिक आपातकाल की आवश्यकता

-अमिताभ शुक्ल

वर्तमान में देश अधिसंख्या जनसंख्या के लिए भीषण आर्थिक त्रासदियों के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में पाँच राज्यों में आई नई सरकारों में से एक राज्य तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने घोषणा तक की कि, "उन्हें 10 लाख करोड़ रुपए के घाटे की अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई है"। कमोबेश यही स्थिति अन्य राज्यों की भी होगी और पूर्व में चुनाव हो चुके अन्य राज्यों की भी है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि। जब देश के अधिकांश राज्यों की सरकारों के कोष खाली हैं और सब खर्च निरंतर प्रत्येक कुछ माहों में निजी संस्थाओं से विशाल कर्ज ले कर चल रहे हैं तब यह ही "देश में आर्थिक आपातकाल का मुख्य आधार" है। जिस पर हाल ही में नागरिकों को अनेकों खर्चों में कटौती का आह्वान भी देश में संसाधनों के अभाव और केंद्र सरकार के पास इसके लिए आवश्यक उपायों के प्रबंधन कर पाने की विवशताओं को स्पष्ट करता है। यह आर्थिक आपातकाल के दूसरे और तीसरे कारण हो गए। अन्य कारण तो पूर्व से ही विद्यमान हैं ही जिनमें भीषण बेरोजगारी, भीषण महंगाई, विशाल जनसंख्या को उनकी विषम आर्थिक स्थितियों में राशन और नकद बांट कर राहत देना आदि। चूंकि सरकारें जनता को रोजगार और आर्थिक सुदृढ़ता द्वारा पारिवारिक बजट की पूर्ति में कोई ठोस सहयोग दे पाने में विफल हैं। यह सब जानते और मानते हैं। बस, सरकारें और मान जाएं। सरकारी फिजूलखर्चों, विलासिता, भारी भ्रष्टाचार पर ठोस निबंधन और कटौती। जनता और देश के दीर्घकालीन कल्याण और विकास के प्रति विजन और प्रतिबद्धता होने पर अवश्य "आर्थिक आपातकाल" का निर्णय लेकर विप्लव अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के ठोस उपाय किए जाएंगे।

सच्चाई यह है कि इस शेरारिंग के नाम पर सरकार ने सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं को छात्रों की उस मौलिक जरूरत से वंचित कर दिया है याने खेल कूद जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिये आवश्यक है। यही स्थिति पुस्तकालयों की है। मैं कितने ही स्कूलों को देख रहा हूँ कि बच्चों के खेल के 1 फुट जमीन नहीं है और स्कूलों को इस शेरारिंग के नाम पर सरकार की अनुमति प्राप्त है तथा यह मनमाना पैसा लूट रहे हैं। शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की चुनौती नहीं है बल्कि चुनौती शिक्षा के स्वदेशीकरण की है। भारत सरकार ने

नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा में ड्राप आउट बहुत घट चुका है लगभग शून्य के बराबर है। क्या कभी सरकार ने इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों है? जो थोड़े भी समर्थ हैं, वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये निजी शिक्षण संस्थाओं में भेज रहे जो समर्थ नहीं हैं, वे लाचार लोग सरकारी स्कूलों में भर्ती कर तथा उनके सामने छोड़कर जाने के अलावा उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं है। अगर छोड़कर जाये तो कहाँ जाएँ क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे न बाहर भेज सकते हैं, न निजी शिक्षण संस्थाओं में भेज सकते हैं। यही कारण है कि हाईस्कूल की शिक्षा में पहुँचते-पहुँचते 55 प्रतिशत छात्र ड्राप आउट हो रहे हैं। जो शिक्षकों की शिक्षा का स्तर है उसे तो क्या कहा जाये। मद्र में नीति आयोग के अनुसार जो शिक्षकों की परीक्षाएँ हुईं उसमें अधिकांश शिक्षक स्वतंत्र अपने विषय में 60 प्रतिशत अंक नहीं पा सके। क्या शिक्षा के इन हालात के चलते शिक्षा का कोई वास्तविक विकास हो सकेगा? मुझे लगता है कि भारत सरकार ने विकेन्द्रीकरण के नाम पर अपना बचाव भर कर लिया है। अब प्राथमिक व स्कूली शिक्षा की हर त्रुटि की जिम्मेदारी शिक्षक-अभिभावक कमेटी की होगी। अभिभावक-शिक्षक कमेटी गाँव में गली खायेंगी और सरकार दिल्ली में बैठकर अपनी पीठ धपथायेगी। बड़े बड़े विज्ञान छात्रावासेगी। शापद ऐसे दिन आने वाले हैं कि अब शिक्षा व शिक्षक का विकास सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं के मालिकों के विज्ञान में मिलेगा परंतु जमीन पर सूखा मैदान होगा।

## पॉलीथीन का आतंक: हमारे भविष्य पर खतरा, जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं

पॉलीथीन हर जगह मसलन सड़कों पर, नालों में, खेतों पर पड़े हुए मिलते हैं। यह नदियों को गंदा करता है और बारिश को नालियों बंद कर देता है। प्लास्टिक टूटकर जहरीला बनता है फिर हमारी फसलों और पानी में मिल जाता है। बच्चों और बुजुर्गों में साँस और पेट की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। कम होते पेड़ पौधे व खातावरण में घुलता जहरीला प्लास्टिक पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होगी। सैकड़ों साल तक विघटित न होने वाला यह अविनाशी हमारे जी का जंजाल बन चुका है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शताब्दी के प्रारंभ में

आवो हवा में जहर घोल देती है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में कार्बन के कण तथा जहरीली गैसों कार्बन डायऑक्साइड निकलती है। तो वहीं दूसरी ओर इसकी राख में विषैली धातुएं पाई जाती हैं। इस जहरीली राख के कण हवा के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं।

पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे लोहा, तांबा एवं खनिज धातुओं के स्थान पर किया जाना शुरू किया गया था। देखते ही देखते यह प्लास्टिक हमारे जीवन में एक आवश्यक वस्तु बन गई है। हम कह सकते हैं कि हम प्लास्टिक युग में प्रवेश कर चुके हैं।

प्लास्टिक और तरह तरह के पॉलीथीन बैग्स के बढ़ते प्रयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए जबर्दस्त खतरा पैदा कर दिया है। आज पूरी दुनिया प्लास्टिक के कचरे की विकराल होती समस्या से त्रस्त है। अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों में तो यह हाल है कि इन देशों में प्रति वर्ष दस लाख टन कचरा प्लास्टिक का निकलता है जिसे किसी भी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। मौसम में अह अचानक बदलाव के पीछे भी वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरे के

### पर्यावरण की फिक्र



डॉ. प्रशांत सिन्हा  
पर्यावरणविद्

कारण जमीन में सैकड़ों वर्ष तक दबे रहने के बावजूद भी नष्ट नहीं होते। साथ ही ये वर्षों तक मिट्टी को अपने इर्द गिर्द ही बांधे रहते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता का तीव्र गति से हास होने लगता है। इस प्रकार वह निश्चित भूभाग अन्नतः अनुपजाऊ हो जाता है। इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर यह पृथ्वी पर होगा तो जानवरों के पेट से लेकर नदी नालों तक को जाम कर देता है। पॉलीथीन जल में अधुलनशील होने के कारण नालियों में फंसकर उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं जिससे गलियों में गंदा पानी भर जाता है। नालियों में इस ठहरे हुए गंदे पानी में सड़ांध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि तमाम कीड़ों तथा मच्छरों के पनपने का आधार है जिससे कई बीमारियों के जन्म लेने का साधन बन जाती है।

अगर इसे जला दिया जाए तो आसमानी संकट पैदा कर देगा क्योंकि इसका धुआँ वायुमंडल को ही नहीं बल्कि ओजोन परत को भी छेड़ने से नहीं चुकता। पॉलीथीन मूलतः एक हाइड्रोकार्बोनिक उत्पाद है। जलाए जाने पर यह अपने आस पास की

रूप में पाए जाने वाले सिंथेटिक कूड़ा कचरे को ही प्रमुख मान रहे हैं। इस प्लास्टिक कचरे के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी प्रभावित भी हो रही है जो अन्नतः हमारी खाद्य श्रृंखला को असंतुलित बना रही है। हालांकि सरकार प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने को संकल्पित दिख रही है लेकिन इसके बावजूद लोगों द्वारा इसका अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक के खात्मे के प्रति हमारी मानसिकता देश के चरित्र पर सवाल खड़ी करती है। हम यह मानकर चलते हैं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें हमारा कोई दायित्व नहीं है। हमें समझना चाहिए कि सरकार हम ही बनाते हैं और यह देश हमारा ही है। सच तो यह है कि अगर आज हम नहीं संभले तो कल सरकार के कोसने के योग्य भी नहीं होंगे। हमें अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं संपूर्ण जीव जगत के हितों को ध्यान में रखते हुए पॉलीथीन के बहिष्कार की दिशा में एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है वरना हमारी जमीन, पानी और सेहत सब भारी कीमत चुकाएंगे।

## योग से चेतना और संगीत से समरसता

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस पर विशेष

21 जून, सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार और वैश्विक सामंजस्य का एक पर्व है। यह दिन दो शक्तिशाली माध्यमों को समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। योग, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है, और संगीत, जो हमें पूरे बढ़ावा दे। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोबायोलॉजी अब प्रमाणित करते हैं कि संगीत और योग दोनों मिलकर अवसाद, चिंता, उच्च रक्तचाप और नकारात्मक विचारों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इनका संयोजन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली युगल है।

### योग: सिर्फ व्यायाम नहीं, एक जीवनशैली का

योग कोई क्षणिक फ़ैशन नहीं है; यह भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन को शांत, आत्मा को मुक्त और जीवन को व्यवस्थित करने की एक संपूर्ण प्रणाली है। 21 जून को जब पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से सराबोर होती है, उसी समय हम योग के माध्यम से अपने भीतर के सूर्य को जागृत करने का संकल्प लेते हैं।

मैं स्वयं हर दिन योग का न केवल अभ्यास करता हूँ, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को भी प्रेरित करता हूँ। योग ने मेरे जीवन में आत्म-नियंत्रण, स्पष्टता और मानसिक स्थिरता लाने में अमूल्य योगदान दिया है। मेरे लिए योग मात्र आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि एक सभ्य जीवन शैली है।

### आज से करें शुरुआत

आद रखें, "शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा दिन आज है।" आज ही से छोटे-छोटे ऋतुओं से शुरुआत करें। हर दिन 15 मिनट प्राणायाम और 15 मिनट सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ। सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटाक्स लें और उस समय का उपयोग योग निद्रा या ध्यान में करें। महीने में एक बार परिवार या टीम के साथ सामूहिक योग सत्र आयोजित करें। अपने गाँव, मोहल्ले या सोशल मीडिया पर #YogaForLife अभियान चलाकर दूसरों को भी प्रेरित करें।

### योग और संगीत: एक वैज्ञानिक सामंजस्य

योग और संगीत, दोनों ही हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं और विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब आप योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो यह न्यूरोप्लास्टिसिटी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाती है और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार करती है। इसी तरह, संगीत सुनना आपके शरीर में 'हेप्टी हार्मोन्स' जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ावा देता है, जिससे अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं में

कमी आती है। ये दोनों अभ्यास मिलकर आपके न्यूरो ट्रांसमीटर को संतुलित करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और आप अधिक शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं।

### योग और संगीत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएँ

योग और संगीत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद सरल और प्रभावी है। सुबह की शुरुआत 10 मिनट के ध्यान और 15 मिनट के योगासन से करें, जो आपके दिन को ऊर्जावान बनाएगा। दोपहर में, जब भी आपको थोड़ा ब्रेक मिले, शांत और मधुर वाद्य संगीत सुनें। यह आपको तरोताजा महसूस कराएगा और काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। शाम को, 5 मिनट की गहरी श्वास के साथ रिलैक्सिंग संगीत सुनें। यह दिनभर की थकान को दूर करने और तनाव को कम करने में सहायक होगा। रात को सोने से पहले योग निद्रा या गाइडेड संगीत ध्यान का अभ्यास करें, जिससे आपको गहरी और आरामदायक नींद आएगी। यह सरल संयोजन आपको एक स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय जीवन जीने में मदद कर सकता है।

### संगीत: वह शक्ति जो शब्दों से परे है

संगीत वह भाषा है जो दिलों को जोड़ती है, सीमाओं को तोड़ती है और आत्मा को छूती है। जहाँ योग आपको आत्म-केंद्रित करता है, वहीं संगीत आपको सामूहिक चेतना से जोड़ता है।

### नव निर्माण की ओर एक कदम

आज का दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि एक नए, संतुलित जीवन की शुरुआत का अवसर है। योग और संगीत को एक साथ अपनाकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ तन, मन और आत्मा—तीनों संतुलन में हों। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप योग को अपने जीवन में उतारें, इसे अपने परिवार में फैलाएँ और समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाएँ। साथ ही, संगीत को सिर्फ मनोरंजन न समझें—इसे जीवन के उत्सव का अभिन्न हिस्सा बनाएँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

### आज की बात



प्रवीण कुलकर्णी  
स्वतंत्र लेखक





# 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के



R.O. No. : 13867/1

## मोदी की गारंटी से आगे बढ़ता छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय, तालनीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

